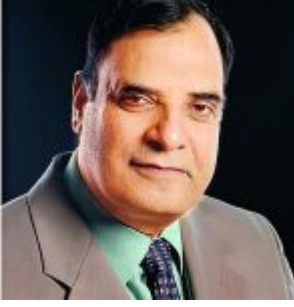


हम कहाँ से और अब कहाँ के माने जाएँ !



अंकित ने हमारे कंप्यूटर प्रिंटर को चेक करने के बाद पूछा – ‘सर, आप कहाँ के हैं’ । मुझे अटपटा लगा । मतलब ? मेरे इस जवाब पर युवक ने संकोच से बोला ‘मतलब दिल्ली के या यू पी, एम पी, बिहार या पंजाब के ? आजकल तो सब यही पूछ रहे हैं’ । सचमुच अंकित भी तीन चार वर्षों से मेकेनिक के नाते हमारे पास आता रहा है । उसने कभी यह सवाल नहीं किया । मैंने उसे सामने कुर्सी पर बैठाया । कहा – पहले कुछ ठंडा पी लो । उसे ग्लास में कोल्ड ड्रिंक देकर मैंने कहा – ” अंकित कैसे बताऊँ । एक छोटे से गांव में जन्म हुआ । पिताजी दूसरे जिले के गांव में शिक्षक थे । फिर एक से दूसरे गांव में तबादले होते रहे । आठवीं की पढाई तक चार स्कूल बदले । फिर उज्जैन पहुंचे तो वहां भी तीन स्कूल में रहा और फिर उज्जैन इंदौर में पढाई पूरी की । पत्रकारिता में इंदौर, भोपाल, दिल्ली, कोलोन (जर्मनी), पटना और फिर दिल्ली में काम करता रहा हूँ । जिन अखबारों का संपादक रहा वहां – दिल्ली, इंदौर, रायपुर, पटना, रांची, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता के स्थानीय संस्करणों में नियम कानून के अनुसार वहां का पता देकर संपादक के नाते नाम छपने से लोग वहां का भी समझा गया ।

दिल्ली ही नहीं पटना या मुंबई या अहमदाबाद में भी कभी यह सवाल होता है कि आप कहाँ के हैं ? अब मेहता सरनेम पंजाब, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में भी होता है । यहाँ तक कि विभिन्न इलाकों में जातियां भी अलग हो सकती है । इसलिए इतना ही समझ में आता है कि भैया अब कहीं का मान लो, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ । ” इतनी लम्बी दास्ताँ सुनकर अंकित ने हँसकर पूछा ‘सर, वो सब ठीक है, यदि इलाज कराना पड़ा तो कहाँ का बता सकेंगे ? केजरीवालजी ने कह दिया है ‘पहले साबित करो कि दिल्ली के हो । ‘ मैंने कहा ‘ भाई इतनी प्रार्थना करो कि इलाज और इस सवाल का जवाब देने की नौबत नहीं आए । ‘ उसे विदा करने के बाद भी मैं विचलित रहा, क्योंकि मेरी तरह लाखों नहीं करोड़ों लोग होंगे । जो भारत ही नहीं दुनिया भर में हैं । उनसे क्या इसी सवाल के सही उत्तर और प्रमाण पर इलाज होगा ?

कोरोना महामारी के संकट ने भारत में प्रादेशिक क्षेत्रीय मुद्दे को गरमा दिया । ये मजदूर मेरा या तुम्हारा, ये सुविधा हमारी या तुम्हारी – इस तरह के दावों से एक खतरनाक मानसिकता भी देश में पैदा हो रही है । यह कोरोना से अधिक घातक है । खासकर सत्ता की राजनीति करने वालों को गंभीरता से सोचना चाहिये । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर एक भारत सशक्त स्वच्छ आत्म निर्भर की बात कर रहे हैं, लेकिन रामलीला मैदान से शिवाजी पार्क के रसों से सत्ता में आने वाले अरविन्द केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी जैसे नेता हमारी दिल्ली – मैं दिल्ली वालों का, आमची मुंबई, मैं मराठा सम्राट, आमार बांग्ला जैसी बातें करके भविष्य के रास्तों पर काँट बिछा रहे हैं । महात्मा गाँधी और डॉक्टर

अंबेडकर का नाम सभी लेते हैं । चलिए गाँधी को ज्यादा नहीं पढ़ा , संविधान की शपथ लेने वालों ने डॉक्टर अंबेडकर को तो थोड़ा पढ़ा होगा ।

फिर भी कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना जरूरी लगता है । डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में नवम्बर 1949 में अपने अंतिम भाषण में कहा था – ” हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए । जब तक उसे सामाजिक आधार न मिले राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं चल सकता । सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है ? वह एक ऐसी जीवन पद्धति है , जो स्वतंत्रता , समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकारती है । बंधुत्व का अर्थ है सभी भारतियों के बीच एक सामान्य भाईचारे का अहसास , जो हमारे सामाजिक जीवन को एकजुट प्रदान करता है । बन्धुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा राष्ट्र एक हो । बन्धुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता रंग की एक परत से अधिक गहरी नहीं होगी । ”

आजकल नेताओं को लगता है कि गाँव , शहर , क्षेत्र , प्रदेश , जाति , धर्म , संप्रदाय , भाषा के नाम पर लोगों को भ्रमित कर तात्कालिक राजनीतिक हित पूरे किये जा सकते हैं । लेकिन इस फॉर्मूले से वे संविधान की भावना का अनादर करते हुए अपनी शपथ को भी झूठी साबित करते हैं । पंचायत से लेकर संसद और सरकार या संगठन को आगे बढ़ाने और बड़े लक्ष्य पाने के लिए एक उदार दिल तथा उदार दिमाग – सोच की जरूरत होती है । छोटी सोच वाले नेता और राष्ट्र कभी बड़ी उपलब्धियां नहीं पा या दिला सकते हैं । जब हम बड़े काम करते हैं तो उनके साथ हमारा कद भी बढ़ता है और हमारे मन भी उदार होते हैं । आज दुनिया में सर्वाधिक युवा भारत में हैं ।

यों सत्तर वर्षों से कहा जाता रहा , लेकिन अब अधिक जरूरी हो गया है कि कोरोना संकट से निपटे हुए सभी क्षेत्रों में उत्पादन में भारी वृद्धि करने , जीवन स्तर ऊँचा करने और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजनीतिक क्षुद्रता से हटकर सम्पूर्ण भारत में एक साथ प्रयास किये जाएँ , ताकि आने वाले तीन से पांच वर्षों में भारत सही अर्थों में आत्म निर्भर कहला सके । यह उद्देश्य केवल घोषणाओं , नारों और फैसलों से पूरा नहीं हो सकता । उन पर अमल के लिए पारस्परिक सहयोग , दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है । आर्थिक नीति का लक्ष्य होना चाहिए- प्रचुरता । आज की दुनिया में अभावों के अर्थशास्त्र का कोई मायने नहीं है । उत्पादन के साथ जन सामान्य की क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए , तभी उत्पादन और उपभोग का चक्र पूरा होगा । इसके लिए सामाजिक सद्भाव , भविष्य निर्माण की राष्ट्रीय भावना जगाये रखने का दायित्व सबका है । इस दृष्टि से भारत सबसे अधिक युवा और सशक्त है । विभिन्न क्षेत्रों में उनके पास अद्भुत क्षमता है । सारी समस्याओं के बावजूद पिछले वर्षों के दौरान पंचायतों में युवाओं और महिलाओं ने ग्रामीण इलाकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का काम किया है । शिक्षा , स्वास्थ्य , आवास और सड़क के साथ उत्पादन एवं रोजगार के लिए नए अभियान चलने पर देखते ही देखते देश का कायकल्प हो सकता है । राजनेताओं को यह समझना और स्वीकारना होगा कि जोड़ तोड़ से कुछ नहीं होगा और लोगों के उत्साहपूर्ण सहयोग के साथ कड़ी मेहनत कोई विकल्प नहीं है ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)